

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-192

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

मंडी, हिमाचल प्रदेश में नए केन्द्रीय विद्यालय

†192. सुश्री कंगना रनौत:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा जहां ये नए केवी स्थापित किए जाएंगे और उनके चयन के लिए मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत करसोग, जोगिंदर नगर, सरकाघाट में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) करसोग, हिमाचल प्रदेश में केवी की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) जिन छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है क्या सरकार उनके लिए एकीकृत शिक्षा सुविधा के तहत जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में करसोग, जोगिंदर नगर और सरकाघाट में नए केवी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) इन केवी के आरंभ होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): नए केन्द्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत प्रक्रिया है। के.वि. मुख्य रूप से पूरे देश में शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए के.वि. खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिनमें मानदंडों के अनुसार नए के.वि. की स्थापना के लिए भूमि और

अस्थायी आवास सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता होगी। ये प्रस्ताव मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होते हैं।

केंद्रीय विद्यालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मानदंडों के आधार पर नहीं खोले जाते हैं। केंद्रीय विद्यालयों को तीन अनिवार्य मानदंडों अर्थात् भूमि की अपेक्षित सीमा (प्रायोजक प्राधिकरण से निःशुल्क), उपयुक्त किराया मुक्त अस्थायी आवास और प्रस्तावित नए केंद्रीय विद्यालय वाले स्थान पर अपेक्षित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या के आधार पर मंजूरी दी जाती है।

वर्तमान में मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 01 केवि सहित हिमाचल प्रदेश राज्य में 26 केवि कार्यात्मक हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग, जोगिंदर नगर और सरकाघाट में नए केवि खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

\*\*\*\*\*